ग्रामीण औद्योगीकरण

✧ डॉ. (श्रीमती) संगीता भटनागर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों को महत्व दिया गया जिनमें पूँजी की आवश्यकता अधिक होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार का ध्यान ग्रामीण औद्योगीकरण की ओर से हटता गया जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत व्यवसाय के रूप में रोजगार का साधन लघु, कुटीर एवं ग्राम उद्योग ही रहा है। परन्तु अब शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने की नीति के फलस्वरूप साहसियों का ध्यान इन उद्योगों की स्थापना की ओर आकर्षित हुआ जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग संभव हो सकेगा। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की आवश्यकता, गामीण उद्योग लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा इनके मार्ग में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करने सम्बन्धी सुझावों की विवेचना की गई है।

ग्राम विकास बिना औद्योगीकरण अधूरा है तथा औद्योगीकरण का प्रभाव ग्राम विकास पर पड़ना स्वाभाविक है। ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु आधारभूत संरचना के विकास की आवश्यकता होती है। इस संरचना के निर्माण में शासकीय एवं अशासकीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति में भी ग्रामीण उद्यमों की स्थापना तथा प्रोत्साहन को महत्व दिया है। श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना ही नीति का प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहा है। ग्रामीण उद्योग श्रम प्रधान होते है। सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य मानवीय कल्याण में वृद्धि करना तथा ग्रामीण श्रमशक्ति का कुशलतम उपयोग कर रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति हेतु आय उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य हेतु शासन ग्रामीण साहसियों को श्रम उपलब्ध कराता है। इससे ग्रामीणों का शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास रोकने में भी सहायता मिलती है।

xzkeh.k vkS|ksxhdj.k dh vko';drk%

ग्रामीण क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल श्रम शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। औद्योगिक इकाईयों में दोनों प्रकार की श्रम शक्ति का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। जनसंख्या बढ़ने से कृषि क्षेत्र में खेतों का आकार छोटा हुआ है, तथा भूमि के विभाजन एवं उपविभाजन के कारण भूमि पर श्रमशक्ति का दबाव बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाने से वहाँ के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें तथा कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से जो कुटीर उद्योग धंधे पनप सकते हैं उनमे प्रमुखतः लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, कृषि आधारित उद्योग, प्राकृतिक संपदा पर आधारित तथा वन संपदा पर आधारित उद्योग हैं। अन्य प्रकार के उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक सामग्री का हस्तांतरण खर्चीला होगा। अतः ग्रामीण उद्योगों की स्थापना किया जाना ही उपयुक्त है। शासन की नीति तभी सफल हो सकती है जब सरकार कुटीर उद्योग इकाईयाँ स्थापित करने हेतु साधन एवं मार्गदर्शन दोनों उपलब्ध कराये।

xzkeh.k m|ksx&dqVhj ,oa y?kq m|ksx%

कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना से रोजगार की तलाश में निकले युवकों में पलायन की प्रवृति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी इससे स्थानीय श्रमशक्ति का कुटीर उद्योगों में अधिक उपयोग होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग तथा कुटीर उद्योगों को पर्यायवाची माना जाना है। वर्ष 1950 के राजकोषीय आयोग ने उन उद्योगों को कुटीर उद्योग माना है जिनमें केवल परिवार के सदस्य कार्य करते हैं। इससे विपरीत लघु उद्योगों में वे उद्योग शामिल किये हैं जहाँ मजदूरी के बदले काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 से 50 तक होती है। इनकी परिभाषाओं में परिवर्तन अब निवेश की सीमा से सम्बन्धित है। ग्रामों में परम्परागत उद्योगों में कुछ विषिश्ट जातियों तथा समुदायों द्वारा चलाये गये उद्योगों को शामिल किया जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इनमें उन्हें कौशल प्राप्त है किन्तु तकनीकी परिवर्तन, विपणन में सहायता तथा कौशल उन्नयन की आवश्यकता बनी हुई है। गैर परम्परागत ग्रामीण उद्योगों में सरकार ने सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करके निवेश किया है। इसमें अधः संरचना, परिवहन तथा आवास निर्माण में सहायक उद्योग शामिल है।

विभिन्न ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग संस्था का गठन किया था। यह ग्रामीण अंचल में रोजगार के साधन सृजन करने हेतु तथा उपलब्ध साधन स्रोतों तथा नैसर्गिक सम्पत्ति के अति उत्तम उपयोग हेतु गठित एक विधि विहित संस्था है। इसके माध्यम

---

lgk;d ik/;kid ¼vFkZ'kkL=½] 'kkldh; LukrdksÙkj egkfo|ky;] nfr;k ¼e0iz0½

से स्थापित उद्योगों में ग्राम स्तर के शिल्पकारों, बुनकरों, उद्यमियों व व्यवसायियों को अपनी विशिष्टता के साथ बढ़ने के अवसर मिल रहे है।

xkeh.k y?kq dqVhj m|ksx esa lEHkkouk,¡ %

किसी स्थान पर इन उद्योगों की संभावना स्थानीय मांग व पूर्ति, संसाधन की उपलब्धता, स्थानीय कौशल, भौगोलिक दशाओं, श्रम, वित्त, परिवहन व बाजार की उपलब्धता सम्बन्धी सुविधाओं पर निर्भर करती है। भारत में कृषि प्रधान होने के कारण कृषि व सम्बन्ध व्यवसायों में निवेश किया गया। अतः कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कृषि पदार्थों, वन्य उपजों व कौशल पर आधारित परम्परागत लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई। देश में परम्परागत ग्रामीण उद्योगों के अतिरिक्त नवीन कुटीर व लघु उद्योग के रूप में सेवा उद्योग सम्बन्धी सेवाएँ, यांत्रिकी इन्जीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग सम्बन्धी सेवा क्षेत्र में अपार सम्भावनाएँ विद्यमान है।

कृषि आगतों की पैदावार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सम्भावनाओं को प्रशस्त किया है। वनोपज पर आधारित उद्योगों में कागज, कत्था, गोंद पैकिंग उद्योग, स्टेशनरी, अगरबत्ती, जड़ी बूटी, उद्योग प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान पुरातन धरोहर को संरक्षित करके ग्रामीण पर्यटन उद्योग का विकास करके ग्रामीण औद्योगीकरण की गति तेज की जा सकती है।

xkeh.k m|ksx dh leL;k,¡ %–1. कच्चे माल की समस्या। 2. वित्त की समस्या। 3. श्रम सम्बन्धी समस्याएँ। 4.मशीन व उपकरणों के प्रशिक्षण उपलब्धता व मरम्मत की समस्या। 5. विपणन समस्याएँ (ग्राम उत्पाद की प्रतिस्पर्द्धा, नया पैटर्न, उत्पादन प्रक्रिया में अद्यतन परिवर्तन इत्यादि) 6. बुनियादी सुविधाओं का अभाव। 7. प्रबंधकीय क्षमता कम होना। 8. परामर्श सुविधाओं का अभाव।

प्रशिक्षण व अनुसंधान पर ध्यान न दिए जाने से लागत में कमी व साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण उत्पादों का प्रभावपूर्ण विज्ञापन किया जाना आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुशल सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण संसाधनों का अपव्यय नहीं रोका जा पा रहा है।

xkeh.k vkS|ksxhdj.k gsrq lq>ko %

शासन तथा विकास एजेन्सियों द्वारा उद्यमिता की भावना का विकास किया जाना आवश्यक है। नवीन साहसियों को तकनीकी शिक्षा, वित्तीय संसाधन व मार्ग दर्शन द्वारा उन उद्योगों की स्थापना हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए जिन वस्तुओं तथा सेवाओं की क्षेत्र में मांग है। ऋण एवं अनुदान के उपरान्त भी सतत् निगरानी रखी जानी चहिए जिससे ग्रामोद्योग इकाईयाँ रूग्ण न हो सकें।

ग्रामीण दस्तकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं को आकर्षक पैकेजिंग प्रक्रिया में ढालने हेतु विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए। उद्यमियों को लागत न्यूनतम करने सम्बन्धी नवप्रवर्तन अपनाने को तैयार एवं गुणवत्ता सुधारने के उत्सुक उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन सुविधाओं के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए। औद्योगिक जानकारी हेतु प्रशिक्षण निरन्तर होना चाहिए। कभी कभार के शिविर ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु वातावरण निर्मित नहीं कर सकेगें। भारत को शक्तिशाली बनाने में ग्रामीण औद्योगीकरण एक मजबूत विकल्प सिद्ध होगा।

lUnHkZ xzUFk lwph %&

1. Sen, K.K. - Rural Industrialization in India, S-Chand & Sons, Delhi
2. Taori, K. Singh - Rural Industrialization - A P Plan for future, Vikas Publishing house Pvt. Ltd., New Delhi.
3. प्रसाद, अवध – ग्रामीण विकास का एक आयाम, प्रिन्टवैल, जयपुर
4. धींगरा, ईश्वर – ग्रामीण अर्थव्यवस्था – एस0 चाँद
5. यादव सुबै सिंह, यादव, सत्यभान सिंह – ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन, सबलाईम पब्लिकेशन, जयपुर
6. खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण अर्थ विषयक पत्रिका, मुंबई।